अगर आप मन से स्वतंत्र है, तो आप वास्तव में स्वतंत्र है।
– अज्ञात

अर्थव्यवस्था के लिए नई मुसीबत

अमेरिका मई में लॉकडाउन हटाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इस चुनावी साल में अपनी अर्थव्यवस्था को जल्दी पटरी पर लाना चाहते हैं। चीन में कई कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है, हालांकि संक्रमण के नए मामलों ने वहां एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है।

ममता वर्मा।

शुक्र है कि तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और उसके सहयोगियों के बीच तेल उत्पादन में कटौती को लेकर समझौते पर सहमति बन गई है। वरना आने वाले दिनों में इनमें से कुछेक दिवालिया हो जाते और इस संकट के दौर में विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाती।

महामारी के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की मांग में आई कमी को देखते हुए इसकी कीमत स्थिर रखने के लिए उत्पादन में 10 फीसदी कटौती का फैसला लिया गया है। मेक्सिको के अड़े रहने से इस समझौते में देरी हुई हालांकि बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने उसको भी कटौती के लिए राजी कर लिया। महामारी का असर दिखने से पहले ही सऊदी अरब और रूस में तेल कीमतों को लेकर विवाद चल रहा था और रूस को सबक सिखाने के लिए सऊदी अरब ने अपना प्रॉडक्शन बढ़ा दिया था।

इसके पहले चीन–अमेरिका ट्रेड वॉर ने वर्ल्ड इकनॉमी का बाजा बजा रखा था। अभी ज्यादातर देशों में लॉकडाउन है। आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हैं। शुरू में सारी सरकारों को लगा कि वायरस का हमला थोड़े समय की बात है। इसका असर कम होते ही सब कुछ पटरी पर लौट आएगा। ऐसी गलतफहमियों के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। निकट भविष्य में कोविड–19 का प्रकोप खत्म होने की संभावना नहीं दिख रही। ऐसे में सारे देशों का रुख यही है कि आर्थिक गतिविधियां बीमारी से जूझने के क्रम में ही शुरू कर दी जाएं वरना आने वाले दिनों में एक बड़ी आबादी के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी।

अमेरिका मई में लॉकडाउन हटाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इस चुनावी साल में अपनी अर्थव्यवस्था को जल्दी पटरी पर लाना चाहते हैं। चीन में कई कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है, हालांकि संक्रमण के नए मामलों ने वहां एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। इस बीच जापान ने अपनी कुछ कंपनियों को चीन से बाहर शिफ्ट करने का फैसला किया है और उनके लिए एक पैकेज घोषित करने वाला है। भारत ने भी तय कर लिया है कि एक तरफ कोविड–19 के खिलाफ मोर्चा खोले रखा जाए, दूसरी तरफ सावधानी बरतते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएं ताकि लोगों के हाथ में नकदी पहुंचे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और उद्योग संगठनों से बातचीत के बाद एक एग्जिट प्लान तैयार किया है। प्रस्ताव है कि सड़क बनाने और आवश्यक वस्तुओं के निर्माण से जुड़े उद्योगों को पहले चरण में उत्पादन शुरू करने की इजाजत दी जाए। कुछ जरूरी सेवाओं की अनुमति मिले, जैसे ठेले पर सब्जी और फलों की बिक्री।

फ्रिज, टीवी, एसी रिपेयर करने वालों, धोबी, बढ़ई और इलेक्ट्रीशियन के काम पर से रोक हटाने का भी प्रस्ताव है। किसानों को कई छूटें पहले से मिली हुई हैं। कटाई के लिए उन्हें और सहूलियतें दी जाएंगी। उम्मीद करें कि इससे बीमारी को सीमित रखने में कोई अड़चन नहीं पेश आएगी और आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी।

नियतकालिक

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

पदार्थ में यह अवस्था कुछ–कुछ अलग होती है। एक ठोस पदार्थ अधिकांश रुप से नियतकालिक होता है, किसी ठोस पिंड में अणुओं के व्यवस्था क्रम की नियतकालिकता को ग्रहण करने पर इसके कई सारे गुण–धर्मों को काफी संतुष्टपूर्ण तरीके से समझने के सुराग मिल सकेंगे। काल में आवधिकता का यह एक उदाहरण है, जो अत्याधिक लाभप्रद है। "पुनः, पुनः, पुनः" का आदर्श पदार्थ के स्थान पर तो, सही है लेकिन जीवन में यह सही नहीं है। दूसरे शब्दों में, जीवन में कुछ भी "पुनः" नहीं होता। आगे का उल्लेख इस पहलू पर और प्रकाश डालता है। जीवन में घटनाएं नियतकालिक नहीं होती है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु– यह सभी घटनाएं सामान्य जीवन में केवल एक बार होती है। हो सकता है कभी कभी बीमारी या दुर्घटना के कारण कुछ लोग इनमें से एक या दो परिवर्तनों को खो देते हों।

संपादकीय

सबको मिले लाभ

मॉनसून के मिजाज और लॉकडाउन की वजह से कृषि क्षेत्र की स्थिति कोढ़ में खाज जैसी हो गई है। ऐसे में कृषि ऋण की वसूली सरकार को कम से कम 6 महीने के लिए रोक देनी चाहिए और उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगाना चाहिए। खरीफ की फसल के लिए किसान जो भी ऋण लेना चाहे उस पर कोई ब्याज न हो तो बेहतर है।

खेतिहर मजदूरों के संकट को दूर करना भी जरूरी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण अंचल में खेतिहर मजदूरों की संख्या 14 करोड़ 43 लाख है। एनएसओ के डाटा के अनुसार वर्ष 2012 से 2018 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बढ़ी है। इन 6 वर्षों में तीन करोड़ और लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं। बड़े राज्यों में बिहार, झारखंड और ओडिशा में गरीबों की संख्या इन 6 वर्षों में सबसे ज्यादा बढ़ी है। हालांकि बंगाल तमिलनाडु और गुजरात में गरीबों की संख्या में कमी भी दर्ज की गई है। यदि देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तो खेतिहर मजदूर भी परेशानी की स्थिति में रहेगा। सरकार को इस बात पर विचार करके तुरंत एक ऐसी कार्य योजना बनानी चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की आमदनी बढ़े, साथ ही खरीफ की फसल की बुवाई भी बेहतर तरीके से हो जाए।

अगर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए बेहतर योजना नहीं बनाई तो देश में खरीफ की फसल के उत्पादन में गिरावट दर्ज हो सकती है। इधर सरकार ने कृषि क्षेत्र को कुछ छूटें जरूर दी हैं, लेकिन देखना होगा कि उसका लाभ हर किसी को मिले। संकट के इस दौर में किसान–मजदूरों को आर्थिक मदद के साथ–साथ भावनात्मक संबल की भी जरूरत है। पूरे देश को अभी इनके साथ खड़ा होना चाहिए।

देश में जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से किसानों को रबी की फसल की कटाई और बिक्री, गन्ने की फसल की बिक्री व भुगतान और आलू की फसल की निकासी की चिंता लगी है।

किसानों के साथ पूरा देश

राजीव त्यागी।

औद्योगिक इकाइयां और अन्य सभी संस्थाएं अपना मुकम्मल पाने के लिए इंतजार कर सकती हैं, लेकिन खेती इंतजार नहीं कर सकती। कोरोना के संक्रमण और आर्थिक बदहाली की वजह से चारों तरफ बेचैनी का माहौल है, पर सबसे ज्यादा घबराहट ग्रामीण क्षेत्र में है। देश के किसान और खेतिहर मजदूर सरकार की तरफ देख रहे हैं। वे इस आस में बैठे हैं कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र को इस वायरस के संक्रमण से भी बचाएगी, साथ ही इसकी वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो गहरा आघात लगा है, उससे उबारने का काम भी करेगी।

देश के आर्थिक हालात की समीक्षा करें तो स्थिति कोरोना का झटका आने से पहले भी निराशाजनक थी। पिछले 11 वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सबसे कम, और खेती की विकास दर पिछले चार वर्ष में सबसे कम। देश में जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से किसानों को रबी की फसल की कटाई और बिक्री, गन्ने की फसल की बिक्री व भुगतान और आलू की फसल की निकासी की चिंता लगी है। गन्ने की फसल समय पर नहीं कटेगी तो धान, ज्वार, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, बाजरा, मूंगफली, तूर और मूंग जैसी फसलों की बुवाई में भी

दिक्कत आएगी। दूध उत्पादन करने वाले किसान भी बुरी तरह से परेशान हैं। जो सब्जियां और फल जल्दी खराब हो जाते हैं उन्हें उगाने वाले किसान तो बर्बादी के कगार पर हैं। बागवानी की उपज का कोई खरीदार नहीं है, जिसके चलते उनकी सारी फसलें खेतों में ही सड़ रही हैं।

रबी की फसल पकी खड़ी है। लॉकडाउन की वजह से किसान अपनी फसल काटने और बेचने में असमर्थ हैं। इसलिए सरकार को खेती के उपकरण आदि की मरम्मत के लिए तुरंत किसानों को परमिट जारी करने चाहिए। लॉकडाउन हटने के बाद भी संक्रमण फैलने का खतरा बना रहेगा इसलिए व्यक्ति को व्यक्ति से दूरी बनाए रखनी होगी। सरकार को राज्यों में उपलब्ध भू–अभिलेखों और अन्य सूचनाओं के आधार पर तथा संचार साधनों का बेहतर इस्तेमाल करके किसानों से रबी की फसल बेचने को लेकर संपर्क करना चाहिए। किसानों की एक संख्या को दिन–समय आवंटित किया जाए और उसी के अनुसार क्रय केंद्रों पर जाने की सूचना दे दी जाए। इससे क्रय केंद्रों पर भीड़ भी नहीं लगेगी और संक्रमण फैलने का खतरा भी कम होगा। जिस दिन किसान अपनी फसल बेचे, उसी दिन उसको उसके खाते में भुगतान मिलना चाहिए।

रबी की फसल का निस्तारण करने के बाद किसान को तुरंत ही खरीफ की फसल बोने की तैयारी करनी होगी। इसके लिए सरकार को मौसम विज्ञानियों और कृषि विशेषज्ञों के ज्ञान और सूचनाओं का सहारा लेकर देश के किसानों को राह दिखानी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजारों में किन कृषि उत्पादों की मांग बढ़ सकती है, उसके अनुसार ही किसानों को खरीफ फसल को बोने के लिए उत्साहित करना होगा। नगदी फसल लगाने के साथ–साथ खाद्य फसलों को बोने के लिए भी किसानों को निर्देशित करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य फसलों की तंगी देखने को मिल सकती है। केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क में तो कटौती करे ही, साथ ही राज्यों से कहे कि उन्हें डीजल की बिक्री से मिलने वाले टैक्स के एक बड़े भाग की भरपाई केंद्र सरकार करेगी।

सूडोकु नवताल-5311

मध्यम

8	2			6			1	
	6		8	9			7	5
3			1					2
	3		4				6	
6		2		1		4		3
	8				5		2	
2					3			1
5	1			7	6		4	
	9			4			3	6

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5310 का हल

8	6	4	2	7	9	5	3	1
7	3	9	1	8	5	2	6	4
1	5	2	4	3	6	7	9	8
4	1	3	8	6	7	9	5	2
5	8	6	9	2	4	3	1	7
2	9	7	5	1	3	8	4	6
9	4	8	7	5	1	6	2	3
3	7	5	6	4	2	1	8	9
6	2	1	3	9	8	4	7	5

अपना ब्लॉग

हार से हताश थी कांग्रेस

मोहन। जनता विद्यार्थी मोर्चा की इस शानदार जीत से कांग्रेस बेहद परेशान थी। केंद्र में उसकी सरकार बन चुकी थी। कांग्रेस के लोगों ने हमारे जनरल सेक्रेटरी अजीत पांडे से दल–बदल करवा कर कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई जॉइन करवा लिया। यह स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दल बदल का पहला मामला था। डीयू अध्यक्ष बनने के बाद हमने यूनिवर्सिटी में परीक्षा की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन शुरू करवाया और ऐसा करने वाली डीयू पहली यूनिवर्सिटी बनी। इस बीच एबीवीपी को लगने लगा कि अगर हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो हमारी पहचान बन नहीं पाएगी। एक ही विचारधारा के दो छात्र संगठन कैसे चलें, यह भी सवाल था। 1984 का चुनाव जनता विद्यार्थी मोर्चा और एबीवीपी दोनों के जॉइंट बैनर पर लड़ा गया। लेकिन इसके बाद यह तय कर लिया गया कि एक विचारधारा के दो छात्र संगठन नहीं हो सकते। इस फैसले के मुताबिक जनता विद्यार्थी मोर्चा को चुनाव से हटा लिया गया। इसके बाद 1985 से छात्र संघ का चुनाव एबीवीपी ही लड़ने लगा।